स्वामित्व योजना पर सरकार और पटवारी आमने-सामने, मचा घमासान

11 नियमित पटवारी निलंबित, 25 को निलंबन का नोटिस, 32 परिवीक्षाधीन पटवारियों पर बर्खास्तगी की तलवार

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

स्वामित्व योजना के कार्यों में कथित लापरवाही को लेकर राजस्व विभाग की कार्रवाई अब सीधे सरकार और पटवारी संगठन के बीच टकराव का रूप लेती दिखाई दे रही है। गुरुवार को जिला प्रशासन ने स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही के आरोप में छह और नियमित पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इससे जिले में निलंबित किए गए नियमित पटवारियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

इतना ही नहीं, 25 अन्य नियमित पटवारियों को भी निलंबन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं 32 परिवीक्षाधीन पटवारियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किए जाने की बात प्रशासन ने कही है। प्रशासन के अनुसार इन पटवारियों को बर्खास्तगी का आदेश जल्द तामील कराया जाएगा और उनके बस्ते वापस लेने की कार्रवाई भी की जा रही है। एक ओर प्रशासन स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पटवारी संघ ने इस पूरी कार्रवाई की वैधानिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। संघ का कहना है कि जिस तरह से पटवारियों पर काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, उसमें उनके अधिकार और वैधानिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

पटवारी संघ ने कार्रवाई की वैधानिकता पर उठाए सवाल

प्रशासन की कार्रवाई के बाद पटवारी संघ ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पटवारी संघ के प्रवक्ता आशीष सक्सेना के अनुसार, संघ का मुख्य सवाल स्वामित्व योजना में पटवारियों को दिए जा रहे कार्यों की वैधानिक प्रकृति को लेकर है।सक्सेना का कहना है कि जमीन के हस्तांतरण और उससे जुड़े वैधानिक कार्यों के लिए कानून में सक्षम अधिकारी की व्यवस्था है। ऐसे में पटवारी को किस नियम के तहत हस्तांतरण से संबंधित कार्य के लिए निष्पादन अधिकारी बनाया जा रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए।संघ का कहना है कि यदि सरकार और विभाग नियम-कानून के तहत यह स्पष्ट कर दें कि पटवारी को कौन-सा कार्य किस अधिकार के तहत करना है और उसकी वैधानिक जिम्मेदारी क्या है, तो पटवारी काम करने के लिए तैयार हैं।यानी विवाद काम करने या न करने से ज्यादा अब इस सवाल पर पहुंच गया है कि पटवारी से जिस काम को कराया जा रहा है, उसकी कानूनी जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

कार्रवाई का दायरा बढ़ता गया

स्वामित्व योजना के काम को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। पहले पांच नियमित पटवारियों को निलंबित किया गया था। गुरुवार को छह और नियमित पटवारियों को निलंबित किए जाने के बाद यह संख्या 11 हो गई है। इसके साथ ही 25 नियमित पटवारियों को निलंबन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।प्रशासन की कार्रवाई का सबसे गंभीर असर परिवीक्षाधीन पटवारियों पर दिखाई दे रहा है।

32 परिवीक्षाधीन पटवारियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रशासन का कहना है कि बर्खास्तगी के आदेश जल्द तामील कराए जाएंगे और संबंधित पटवारियों के बस्ते वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है।प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वामित्व योजना के कार्यों में आगे भी यदि किसी पटवारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छह-सात बार ज्ञापन, फिर भी समाधान नहीं

पटवारी संघ के प्रवक्ता का दावा है कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर पर कई बार अधिकारियों और सरकार को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। संघ के अनुसार छह से सात बार ज्ञापन देकर अपनी आपत्तियों और शंकाओं से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला।संघ का कहना है कि पटवारी स्वामित्व योजना के काम का विरोध केवल काम से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि उन्हें ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिनकी वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।पटवारी संघ का दावा है कि इस संबंध में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। ऐसे में संघ चाहता है कि सरकार पहले कानूनी स्थिति स्पष्ट करे और उसके बाद ही कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए।



परिवीक्षाधीन पटवारी बने सबसे बड़ा मुद्दा

इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा 32 परिवीक्षाधीन पटवारियों को लेकर है। संघ का आरोप है कि परिवीक्षा अवधि में काम कर रहे कर्मचारियों को निलंबन अथवा बर्खास्तगी की कार्रवाई के जरिए दबाव में लिया जा रहा है।पटवारी संघ के प्रवक्ता का कहना है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए उन पर कार्रवाई का असर व्यापक होगा। संघ ने आरोप लगाया कि उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है और संगठन की एकजुटता को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर अलग से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का मूल पक्ष यह है कि स्वामित्व योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

'काम करने को तैयार हैं, नियम स्पष्ट करें'

पटवारी संघ ने अपनी स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही है। संघ का कहना है कि यदि नियमों की स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है और यह बताया जाता है कि पटवारी किस वैधानिक अधिकार के तहत संबंधित कार्य करेंगे, तो उन्हें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है।इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर विभाग और पटवारी संगठन के बीच संवाद के जरिए विवाद का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है।एक तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं का निर्धारित समय में क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। दूसरी तरफ कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी भी है कि उन्हें सौंपे गए कार्य नियमों के अनुरूप किए जाएं। ऐसे में यदि किसी कार्य की वैधानिक जिम्मेदारी को लेकर ही कर्मचारी और विभाग आमने-सामने हैं, तो इसका समाधान कार्रवाई से ज्यादा स्पष्ट आदेश और नियमों की व्याख्या से निकल सकता है।

सिर्फ छिंदवाड़ा का मामला नहीं

पटवारी संघ का दावा है कि इस तरह की कार्रवाई केवल छिंदवाड़ा जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी पटवारियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है।संघ इसे प्रदेशव्यापी मुद्दा बता रहा है। संगठन का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी शंकाओं का निराकरण नहीं किया तो इसका असर राजस्व संबंधी कामकाज पर पड़ सकता है।वहीं प्रशासन की ओर से संकेत साफ है कि स्वामित्व योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे आने वाले दिनों में विवाद और बढ़ने की आशंका है।

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल का कलेक्टरों को सात दिनों का नोटिस

मुख्य सचिव अशोक वर्णमाल ने कलेक्टरों को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अगर कलेक्टर पटवारियों से काम करा पाने में सफल नहीं हुए तो कलेक्टरो को भोपाल बुलाया जाएगा। वीडियो कॉंफ्रेंस के जरिए यह चेतावनी जारी की गई है। अगर कलेक्टर ने काम नहीं किए तो उनके ऊपर भी कार्यवाही की गाज गिर सकती है। यही कारण है कि अब जिला कलेक्टर पटवारियों पर सख्ती दिखा रहे है। यह बात उल्लेखनीय है कि दरअसल ये वहीं पटवारी है जो सीधे तौर पर किसानों से जुड़े होते है और भ्रष्टाचार और हेराफेरी के कामों में अधिकाधिक मात्रा में संलिप्त होते है। सम्पति की जांच की जाए तो पूरे प्रदेश के पचास प्रतिशत से ज्यादा पटवारी करोड़पति श्रेणी में आते है और आय से अधिक सम्पति जोड़कर रखे है। अगर स्वामित्व योजना जैसे गांव में आबादी की जमीन का मालिकाना हक देने की योजना है जिसे मुख्य सचिव सात दिनों में प्रोग्रेस चाहते है। अगर पटवारियों ने सहयोग नहीं किया तो कलेक्टर और तहसीलदार दोनों ही मुख्य सचिव के रडार पर है। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। परंतु अभी तो सीधा निशाना पटवारियों पर है जिसके लिए तरकश से पहला बाण छोड़ा जा चुका है।

पांडू पिपरिया पंचायत के बांसडोंगरी में नाली निर्माण पर आरोप

नाली के नाम पर बिछा दी कांक्रीट, ग्रामीणों ने उठाए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल

हरिभूमि न्यूज ⏭ तामिया

तामिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और आवश्यकता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई पंचायतों में जरूरत के अनुरूप विकास कार्य कराने के बजाय केवल राशि खर्च करने और निर्माण की खानापूर्ति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला जैतपुर सेक्टर की ग्राम पंचायत पांडू पिपरिया के ग्राम बांसडोंगरी में सामने आया है, जहां नाली निर्माण के नाम पर कंक्रीट बिछाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर निर्माण कराया जा रहा है, वहां न तो घरों का गंदा पानी आता है और न ही जल निकासी के लिए नाली की आवश्यकता है। इसके बावजूद नाली निर्माण के नाम पर शासकीय राशि खर्च किए जाने से निर्माण की उपयोगिता पर





नाली की जगह कंक्रीट की पतली परत

ग्रामीणों के अनुसार नाली निर्माण का मूल उद्देश्य घरों और गलियों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित करना तथा गांव में स्वच्छता बनाए रखना है। लेकिन बांसडोंगरी में जिस स्थान पर नाली निर्माण कराया जा रहा है, वहां नाली की आवश्यकता ही नजर नहीं आती। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली बनाने के बजाय जमीन पर पतली सी कंक्रीट की परत बिछाई जा रही है। इसे देखकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसे नाली निर्माण किस आधार पर माना जा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर हो रहा निर्माण निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच किए जाने की जरूरत है। यदि नाली निर्माण की तकनीकी स्वीकृति दी गई है तो मौके पर वास्तविक रूप से नाली का स्वरूप क्यों नजर नहीं आ रहा, यह जांच का विषय है।

निर्माण कार्य में सामग्री के इस्तेमाल को लेकर भी ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार नाली निर्माण में रेत की जगह क्रेशर डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले ही कंक्रीट की परत बेहद पतली दिखाई दे रही है और उसमें निर्धारित सामग्री के स्थान पर क्रेशर डस्ट का उपयोग किए जाने से निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है।ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच करें और निर्माण की मोटाई तथा तकनीकी मापदंडों का सत्यापन कराएं।

दूसरी पंचायत के मजदूरों को काम देने का आरोप

निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिलने को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली निर्माण में दूसरी पंचायत के मजदूरों को काम पर लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मजदूर रोजगार के लिए दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं, जबकि पंचायत में निर्माण कार्य चलने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया जा रहा।ग्रामीणों के अनुसार यदि पंचायत के पास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मजदूरों को रोजगार देने का अवसर है तो उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस मामले में पंचायत द्वारा किस आधार पर मजदूरों का चयन किया गया, इसकी भी जांच की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने पंचायत के टैंकर के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पंचायत का टैंकर ग्रामीणों को सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं कराया जाता, लेकिन निर्माण कार्य में उसका उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि पंचायत का संसाधन शासकीय और सार्वजनिक उपयोग के लिए है तो उसके उपयोग का स्पष्ट रिकॉर्ड होना चाहिए।

तकनीकी अमले की भूमिका पर भी सवाल

बांसडोंगरी में नाली निर्माण की स्थिति सामने आने के बाद एस्टीमेट तैयार करने वाले उपयंत्री, तकनीकी स्वीकृति देने वाले सहायक यंत्री और वर्तमान में पदस्थ उपयंत्री की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मौके पर नाली की आवश्यकता नहीं थी तो आखिर किस आधार पर इसका एस्टीमेट तैयार हुआ और तकनीकी स्वीकृति कैसे मिली।ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर हो रही कथित खानापूर्ति से संबंधित तकनीकी अमला अनजान नहीं रह सकता। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि निर्माण की स्वीकृति किस आधार पर दी गई और मौके पर स्वीकृत मापदंडों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं।उपयंत्री से संपर्क नहीं हो सकानाली निर्माण को लेकर संबंधित उपयंत्री का पक्ष जानने के लिए मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन ऑपरेट नहीं होने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। विभागीय अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गर्भ में नवजात ने तोड़ा दम

23 सालो में क्यों नहीं लाये एमडी डॉक्टर, स्टाफ, युवक कांग्रेस युवक कांग्रेस ने 2 घंटे किया प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज ⏭ सौंसर

सौंसर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल एक बार फिर उस समय खुल गई, जब स्वास्थ संसाधनों और डॉक्टरों के अभाव में एक गर्भवती महिला के नवजात शिशु ने मां की कोख में ही दम तोड़ दिया। कहान क्षेत्र के सरसावरी गांव निवासी गर्भवती महिला रेणुका घोड़मारे को समय पर सही इलाज न मिलने के कारण यह दिल दहला देने वाली घटना घटी है।

युवक कांग्रेस और क्षेत्र वासियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एनेस्थीसिया, सीजर स्पेशलिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ (गाइनेकोलॉजिस्ट) और एमडी डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण कई लोगों मासूमो की जानें जा चुकी हैं।



23 साल गुजर गए नहीं ला पाए 1 एमडी डॉक्टर

गौरतलब है कि सौसर अस्पताल को 100 बिस्तरों (100 बेड) का दर्जा मिले 23 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। इसके बावजूद आज भी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन, एक्स-रे रिपोर्ट,की आधुनिक सुविधा, ईसीजी मशीन, नियमित गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर और एमडी ऑर्थो डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी है। आलम यह है कि जरा सी स्वास्थ्य जटिलता या दुर्घटना होने पर भी मरीजों को मजबूरन नागपुर या छिंदवाड़ा रेफर करना पड़ता है।पिछले 2 दशकों से अधिक समय से बदहाल इस स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने में शासन और क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक दलों के जिम्मेदार नेता पूरी तरह नकारा साबित हुए हैं।इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुई पीड़ित महिला रेणुका ने शासन-प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि, अस्पताल में पुख्ता चिकित्सा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि जो असहनीय पीड़ा मुझे झेलनी पड़ी है, वह भविष्य में किसी अन्य महिला को न देखनी पड़े।

इनका कहना है

बीएमओ सौंसर डॉ. रूपेश बोकड़े ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि यह महिला का दूसरा सीजर केस था, अस्पताल में सुविधा नहीं होने के चलते मरीज को रेफर कीया जा रहा था। मेरी स्वयं की खुशी से निजी अस्पताल में गए थे।

अस्पताल गेट पर युवा कांग्रेस का धरना, तीखा आक्रोश

इस अमानवीय लापरवाही और जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में गुरुवार दोपहर युवा कांग्रेस, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मुख्य गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस नेताओं ने पिछले 23 सालों से सौसर अस्पताल की उपेक्षा पर अपनी भड़ास निकाली। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और अस्पताल में तत्काल प्रभाव से सभी बुनियादी सुविधाएं बहाल करने की मांग की। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशांत धुर्वे, जिला एनएसयूआई अध्यक्ष जिमी टाकभावरे, यूका तहसील अध्यक्ष राजा बोढे, अनमोल आकोटकर,पवन पन्नासे,योगेश अम्बाडरे आदि ने क्षेत्र के भाजपा नेताओं एवं भाजपा सरकार से जवाब मांगा है कि पिछले 23 वर्षों में अब तक सौसर अस्पताल को 100 बेड की सुविधाये डॉक्टर, संसाधन मशीनरी क्यों नहीं ला पाए है।

महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट ने मनाया वायु सेना दिवस

जुन्नारदेव। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव के एनसीसी कैडेटों द्वारा गुरुवार 8 अक्टूबर को 24 एमपी बटालियन छिंदवाड़ा के निर्देशानुसार एवं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संगीता वाशिंगटन के मार्गदर्शन में वायु सेना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती का पूजन के साथ किया गया साथ ही अमर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर ए के टांडेकर द्वारा वायु सेना के सौर्य पराक्रम और स्थापना के संबंध में जानकारी दी।

जनसुनवाई में गूंजा खमराकलां के स्थानांतरित सचिव का मामला

जुन्नारदेव। ग्राम पंचायत खमराकलां के ग्रामीण एवं पीड़ित आवेदक उदय नागवंशी मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने ग्राम पंचायत के स्थानांतरित सचिव पुष्प कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ अभद्र व्यवहार, जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती आवेदन सौंपा। शिकायतकर्ता उदय नागवंशी ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल जनपद पंचायत जुन्नारदेव की सीईओ को फोन लगाया, लेकिन काल रिसीव न होने पर उन्होंने तुरंत एसडीएम जुन्नारदेव को दूरभाष पर संपर्क किया। कलेक्टर ने व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत पत्र की प्रति भेजते हुए पूरे मामले में तत्काल व वैधानिक कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। शिकायत आवेदन के अनुसार, गत 2 अक्टूबर को आवेदक जब पेयजल समस्या को लेकर सचिव पुष्प कुमार विश्वकर्मा के पास गया, तो सचिव द्वारा उसके साथ सार्वजनिक रूप से जातिसूचक व अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया गया। आरोप है कि उच्च न्यायालय एवं जिला पंचायत के आदेशों के बावजूद सचिव का स्थानांतरण ग्राम पंचायत रावनवाड़ा होने के बाद भी उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही पिछले 38 महीनों से अवैध रूप से वेतन आहरण तथा डिजिटल सिग्नेचर (DSC) का अनधिकृत उपयोग कर मनरेगा व अन्य शासकीय योजनाओं में गड़बड़ी करने का भी आरोप है। आवेदक व ग्रामीणों की मांग आवेदक एवं ग्राम पंचायत के पंचों व गवाहों, योगेश उईके, मतिभान मर्सकोले, सुनील वनस्पतिया व प्रमिला बंसल ने सचिव के विरुद्ध अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने, ग्राम पंचायत खमराकलां के समस्त वित्तीय लेन-देन की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोपी सचिव को तत्काल प्रभाव से रिलीव करने की मांग की है।

80 लाख की जमीन खरीदी के मामले में पटवारी याचना सोनी को नोटिस

छिन्दवाड़ा। छिंदवाड़ा नगर तहसील में पदस्थ पटवारी याचना सोनी के नाम से जुड़ी करीब 80 लाख रुपये की जमीन खरीदी का मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने और मामले में कुछ बिंदु संदिग्ध पाए जाने के बाद एसडीएम छिंदवाड़ा ने पटवारी याचना सोनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसकी सम्पूर्ण जांच के लिए अब नोटिस जारी कर पटवारी याचना सोनी से जवाब तलब किया गया है। यदि अनुमति प्राप्त करने अथवा आय से अधिक संपत्ति के मामले में जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो याचना सोनी के विरुद्ध एफआईआर भी की जा सकती है। ऐसा होने पर याचना सोनी की सेवा से बर्खास्तगी तय मानी जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्र की किराना दुकानों में यही से होता है सप्लाई

अवैध कट-साईज तेल पैकेटों की दुकानों पर मारा छापा

हरिभूमि न्यूज ⏭ सौंसर

हाल ही में पीपला ना वार के दुकानों में बड़े पैमाने पर कट साइज तेल पैकेट की अवैध बिक्री को लेकर प्रमुखता के साथ में खबर का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद में प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए सभी तेल विक्रेताओं को आवश्यक दिशा गए है।

मिली जानकारी के अनुसार पीपला सौसरक्षेत्र में गैर-मानक (कट-साईज) तेल पैकेटों की अवैध बिक्री और उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ नापतोल विभाग की टीम ने बुधवार को पिपला नारायणवार में बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने थोक और चिल्लर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों व गोदामों की सघन जांच की। कार्यवाही में 13 लीटर के बंडल में 750 ग्राम और 800 ग्राम जैसे गैर-मानक तेल पैकेटों की धड़ल्ले से बिक्री होने की समस्या को उजागर किया गया था।



जांच के दौरान नापतोल विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। जिसमे तेल की पैकिंग केवल 200 ग्राम/मिली, 500 ग्राम/मिली, 1, 2, 3, 4, 5, 15 और 20 किलो या लीटर में ही होनी चाहिए। वही 650, 750 और 950 ग्राम/मिली जैसे गैर-मानक आकारों की पैकेजिंग और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

200 ग्राम से नीचे के पैकेटों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 5 सितंबर के बाद उत्पादित यदि कोई भी नॉन-स्टोर्ड/गैर-मानक पैकिंग बाजार में पाई जाती है, तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।हालांकि वर्तमान में भी पीपला ना वॉर नगर में गोदाम में बड़े पैमाने पर तेल के कट पैकेट भर कर रखे हुये है। वहीं रात्रि के समय में ग्रामीण क्षेत्र की किराना दुकानों में यही से सप्लाई किया जा रहे हैं।

क्या कहते है अधिकारियों

नापतोल निरीक्षक अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को पिपला नारायणवार में थोक और खुदरा विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई। इस दौरान तेल के पाउच, उनके वजन और अन्य मानकों की बारिकी से पड़ताल की गई। सभी व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तय गाइडलाइन के नियमों के दायरे में ही व्यापार करें।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति पांढुर्णा जिला-पांढुर्णा (म.प्र.)
(Email Id :- apmcpandhurna1964@gmail.com)

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2026-27/476 पांढुर्णा दिनांक 07/10/2026

:- **निविदा आमंत्रण सूचना :-**

कृषि उपज मंडी समिति पांढुर्णा "घ" श्रेणी मंडी द्वारा ई-टेंडरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत संरचना (10 मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा) की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_541600 के अंतर्गत ऑन लाईन निविदायें दिनांक 28.10.2026 को शाम 3:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.co.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट:- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव कृषि उपज मंडी समिति पांढुर्णा जिला-पांढुर्णा

जलाशयों में घटा जलस्तर, निस्तारी तालाबों से सिंचाई पर रोक की मांग, छोटे नदी-नालों में बोरी बंधान बनाने की जरूरत

औसत से कम बारिश ने बढ़ाई चिंता, गर्मी से पहले जलसंकट की आहट

हरिभूमि न्यूज ⏭ तामिया

अत्यधिक वर्षा के लिए पहचाने जाने वाले तामिया क्षेत्र में इस वर्ष औसत से काफी कम बारिश होने का असर अब जलस्रोतों पर साफ दिखाई देने लगा है। बारिश का मौसम बीतने के साथ ही क्षेत्र के जलाशयों, निस्तारी तालाबों और छोटे नदी-नालों में अपेक्षित जलभराव नहीं हो पाया है। हालात अभी से चिंता बढ़ाने वाले हैं। यदि समय रहते जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगामी गर्मी के दिनों में तामिया तहसील को गंभीर पेयजल और सिंचाई संकट का सामना करना पड़ सकता है। लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है।



सौ से अधिक निस्तारी तालाब भी खाली

तामिया जनपद पंचायत की विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से सौ से अधिक निस्तारी तालाब बनाए गए हैं। सामान्य वर्षों में बारिश के बाद इन तालाबों में पर्याप्त पानी जमा हो जाता है और लंबे समय तक ग्रामीणों तथा पशुओं के निस्तार के काम आता है। किसान भी इन तालाबों के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष कम बारिश के कारण अधिकांश निस्तारी तालाबों में अपेक्षित जलभराव नहीं हुआ है।ऐसे में यदि इन तालाबों से सिंचाई के लिए पानी निकालने का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। तालाबों का पानी तेजी से कम होने पर ग्रामीणों के दैनिक निस्तार के साथ पशु-पक्षियों के सामने भी पानी का संकट खड़ा हो सकता है।

जलाशयों में नहीं आया अपेक्षित पानी

कम बारिश का सबसे प्रत्यक्ष और चिंताजनक असर सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए जलाशयों में देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के कोहपानी, बागई, उमरिया, चाखला सहित अन्य जलाशयों में इस वर्ष औसत की तुलना में कम पानी जमा हुआ है। जलाशयों में पानी की कम उपलब्धता का सीधा असर आगामी रबी एवं गर्मी की फसलों की सिंचाई पर पड़ सकता है। वर्तमान में जलाशयों में जितना पानी दिखाई दे रहा है, वह आने वाले महीनों में किसानों की सिंचाई की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, इसे लेकर किसानों में चिंता बढ़ रही है।

निस्तारी तालाबों से सिंचाई पर रोक जरूरी

कम बारिश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और जनपद पंचायत तामिया को निस्तारी तालाबों के पानी को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इस वर्ष इन तालाबों से सिंचाई के लिए पानी लेने पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। तालाबों में उपलब्ध पानी को मुख्य रूप से ग्रामीणों के निस्तार, पशुओं और आगामी गर्मी में पेयजल जरूरतों के लिए सुरक्षित रखा जाना जरूरी है।यदि अभी से तालाबों से पानी निकालने पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गर्मी आने से पहले ही कई तालाब सूखने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इससे गांवों में पेयजल संकट के साथ पशुओं के लिए भी पानी की समस्या खड़ी हो सकती है।

बहते पानी को रोकने की जरूरत

सरकार द्वारा जल संरक्षण को लेकर जल संवर्धन, जलाभिषेक अभियान और 'जल है तो कल है' जैसे अभियानों के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन जल संरक्षण का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब बारिश के दौरान बहकर निकल जाने वाले पानी को स्थानीय स्तर पर रोका जाए। इसके लिए तामिया क्षेत्र के छोटे नदी-नालों में तत्काल बोरी बंधान और अन्य अस्थायी जल संरचनाएं बनाकर पानी रोकने की पहल की जा सकती है।बारिश का पानी नदी-नालों में बहकर निकलने के बजाय यदि छोटे-छोटे स्थानों पर रोका जाए तो इससे आसपास के कुओं और अन्य जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को अभी से स्थान चिन्हित कर आवश्यक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए जाने की जरूरत है।

टुल्लू पंप कनेक्शन पर भी नियंत्रण जरूरी

निस्तारी तालाबों और नदी-नालों से लगातार पानी खींचे जाने पर नियंत्रण के लिए विद्युत विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। प्रशासन को ऐसे जलस्रोतों से टुल्लू पंप चलाने के लिए दिए जाने वाले अस्थायी विद्युत कनेक्शनों पर भी निगरानी और आवश्यकतानुसार रोक लगाने के निर्देश देने होंगे। इससे तालाबों और नदी-नालों से अनियंत्रित तरीके से पानी निकालने पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

अभी नहीं चेते तो गर्मी में बिगड़ेंगे हालात

तामिया में कम बारिश की स्थिति आने वाली गर्मी के लिए खतरे की घंटी है। जलाशयों में कम पानी, निस्तारी तालाबों में घटता जलभराव और गिरता भूजल स्तर भविष्य के संकट का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में संकट आने का इंतजार करने के बजाय अभी से जल प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करना जरूरी है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पीएचई विभाग, तहसीलदार, विद्युत विभाग और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित कर जलस्रोतों की निगरानी की व्यवस्था करनी होगी। निस्तारी तालाबों के पानी को सुरक्षित रखने, छोटे नदी-नालों में बोरी बंधान बनाने और बहते पानी को रोकने के साथ जलस्रोतों से अनावश्यक पानी निकासी पर नियंत्रण किया गया तो आगामी गर्मी में संभावित पेयजल संकट की तीव्रता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिलहाल कम बारिश ने तामिया के लिए स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जल संकट गर्मी में नहीं, बल्कि उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी।

गणेश कुमार तुमड़ाम को गोंडी लोकगीतों पर शोध हेतु पीएच.डी. की उपाधि

पांढुर्णा। सतपुड़ांचल के गोंडी लोकगीतों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, लोकजीवन, सामाजिक सरोकारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर उत्कृष्ट अध्ययन के लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा गणेश कुमार तुमड़ाम को पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई है। श्री तुमड़ाम वर्तमान में पी एम कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पांढुर्णा में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। श्री तुमड़ाम ने अपना शोधकार्य "सतपुड़ांचल के गोंडी लोकगीतों का सांस्कृतिक अनुशीलन" विषय पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुलताई जिला बैतूल की प्राचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. वर्षा खुराना के कुशल मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। अपने शोध ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने सतपुड़ांचल क्षेत्र में प्रचलित गोंडी लोकगीतों के विविध स्वरूपों, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोकपरंपराओं, रीति-रिवाजों, पर्व-उत्सवों, सामाजिक जीवन तथा सामुदायिक चेतना का गहन व विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। गणेश कुमार तुमड़ाम ने अपनी इस अकादमिक उपलब्धि का श्रेय अपनी शोध निर्देशक डॉ. वर्षा खुराना के सशक्त मार्गदर्शन तथा अपने परिवार, सहकर्मियों एवं शुभचिंतकों के सतत सहयोग को दिया है। पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त होने पर महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल अकादमिक भविष्य की कामना की है।



रक्तदान शिविर में एकत्रित हुआ 83 यूनिट रक्त

हरिभूमि न्यूज ⏭ परासिया

पेंच इनमोसा परिवार द्वारा अपने स्थापना दिवस के पावन अवसर पर बड़कुही अस्पताल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ₹रक्तदान-महादान₹ के संदेश को चरितार्थ करते हुए माइनिंग स्टाफ, कर्मचारियों एवं तीन महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस पुनीत कार्य में रिकॉर्ड 83 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिसने पिछले वर्ष के 61 यूनिट के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया।इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति और सराहनीय योगदान:शिविर को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने में अध्यक्ष श्री सादिक अंसारी तथा महामंत्री श्री विकास कुमार शिवहरे के नेतृत्व में पूरी टीम ने जी-तोड़ मेहनत की। इस दौरान राहुल सिंह बघेल, अब्दुल आरिज, मनोज गौतम, नवीन उपाध्याय, नासिर अहमद, प्रेमनारायण कैथवास, सौरभ अवस्थी, राजेश डहरिया, उमेश पहाड़े, मुकेश विश्वकर्मा, धीराज सिंह, वैभव जैन, अंकित अलदक्क, लवकेश सिंह, प्रेम कैथवास, मनीष देहारिया, देवानंद सहानी, अरविंद माहोर एवं ऋतुराज पगारे सहित पेंच इनमोसा परिवार के अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग एवं योगदान रहा।मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म:आयोजन के अंत में संस्था के पदाधिकारियों ने सभी समर्पित रक्तदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर उपलब्ध रक्त किसी का जीवन बचा सकता है, और पेंच इनमोसा परिवार भविष्य में भी ऐसे सामाजिक व मानव सेवा के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

गोटूल ट्राइबल वेलफेयर सोसायटी ने स्थापना दिवस पर किया सराहनीय कार्य

परासिया। गोटूल ट्राइबल वेलफेयर सोसायटी (**GTWS**) के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आज गोटूल भवन, हवाई पट्टी, इमलीखेड़ा में एक अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।सोसायटी द्वारा वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण और अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सच्ची निष्ठा का परिचय दिया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ गोटूल की नींव रखने वाले, भूमिदानदाता परम श्रद्धेय फूलसिंह सल्लाम दादा एवं गोंड राजा बख्तबुलंद शाह समिति के अध्यक्ष आदरणीय सिरपत मर्सकोले जी के द्वारा पौधारोपण कर किया गया।इस प्रेरणादायक अवसर पर गोटूल राजा जाटवा शाह समिति के सदस्य *श्री मुकेश आहके जी, गोटूल संस्था के सदस्य श्री बलवंत बटके जी, श्री राकेश धुर्वे जी, श्री मिथुन धुर्वे जी (फिजिकल ट्रेनर एवं स्पोर्ट्स टीचर), श्री आशाराम वाडिवा जी सुपलाल धुर्वे जी रामदास बट्टी जी प्रवीण घागरे जी सहित समाज के वरिष्ठजनों ने हिस्सा लिया।सभी सदस्यों ने मिलकर भवन परिसर की साफ-सफाई की, कचरा हटाया और कई फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। यह दृश्य देखते ही बनता था, जब सभी एक साथ मिलकर अपने गोटूल भवन को संवार रहे थे।यह कार्यक्रम केवल सफाई तक सीमित नहीं था, यह हमारे समाज की एकता, सेवा भावना और आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और हरा-भरा गोटूल छोड़ने के संकल्प का प्रतीक है।गोटूल ट्राइबल वेलफेयर सोसायटी के इस सराहनीय कदम की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है।





टीबी मुक्त भारत अभियान, पांढुर्णा की 10 ग्राम पंचायतें सम्मानित

पांढुर्णा। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला पांढुर्णा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के तहत 7 ग्राम पंचायतों को स्वर्ण पदक तथा 03 ग्राम पंचायतों को कांस्य पदक एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्रों का वितरण कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ, पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ एवं नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ। अतिथियों ने टीबी उन्मूलन की दिशा में पंचायतों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इसी अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा संयुक्त स्वास्थ्य दल अभियान का शुभारंभ किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिला पांढुर्णा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक तुषार सिंगारे ने उपस्थित जनसमुदाय को टीबी के प्रमुख लक्षणों, समय पर जांच व उपचार के महत्व, बचाव के उपायों तथा निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक व पोषण सहायता की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स को अभियान की टोपी प्रदान कर जन-जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ, पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़, नगर पालिका अध्यक्ष श्री संदीप घाटोड़े, मंडल अध्यक्ष बंटी छगानी, जनपद पंचायत सीईओ विनय प्रकाश ठाकुर सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

इनरव्हील क्लब ने शासकीय स्कूल सीतापार टोला में मनाया स्वच्छता माह



चौरई। इनर व्हील क्लब चौरई द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत शासकीय स्कूल सीतापाटोला में विद्यार्थियों के साथ स्वच्छता माह मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लब की सदस्यों ने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत एवं आसपास के वातावरण की स्वच्छता बनाए रखने के तरीके बताए। बच्चों को स्वच्छता से संबंधित उपयोगी सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की गई तथा उनके सही उपयोग की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। बच्चों की सहभागिता और उत्साह ने पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया। क्लब सदस्यों ने विद्यार्थियों को स्वच्छता को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। इनरव्हील क्लब चौरई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्ष दीपशिखा खंडेलवाल, शीतल राठी, राधा मालवी, राधिका मालानी सहित क्लब की अन्य सदस्य सहित स्कूल के शिक्षक व छात्र उपस्थित रहे।

टी बी उन्मूलन के लिए जोश टीम का गठन



हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। जिला स्वास्थ्य समिति (क्षय) बालाघाट के निर्देशानुसार शासकीय शंकरसाव पटेल महाविद्यालय वारासिवनी में 08 अक्टूबर 2026 को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत टी.बी. मुक्त भारत अभियान के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आनलाईन कार्यक्रम में जोश टीम का शुभारंभ दिल्ली से प्रसारण किया गया। जिसमें महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एस.एस. गेडाम के मार्गदर्शन, एन सी सी अधिकारी डॉ. हेमंत कुमार मण्डाले, कृष्णा परते (रेड रिबन प्रभारी) के नेतृत्व पुरूषोत्तम देशमुख स्वास्थ्य विभाग वारासिवनी, रविन्द्र नागेश्वर एवं पराग पालेवार के सहयोग से एनएसएस, एनसीसी की 20 सदस्यीय निःक्षय टीम की उपस्थिति में आयोजित किया गया। टी.बी. मुक्त भारत अभियान में जोश का शुभारंभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा समस्त मंत्रालय के जनप्रतिनिधि, विभिन्न राज्यों से विधायकगण, अधिकारी एवं 52000 हजार युवा आनलाईन जुड़े.रहे। टी.बी. उन्मूलन के लिए युवा है तैयार, नारों के साथ अभियान का शुभारंभ किया गया। जिसमें युवाओं को नवाचार करे मजबूत रणनीति के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित किया गया। भारत को टी.बी. मुक्त बनाने के लिए टी.बी. मुक्त भारत ऐप तैयार किया गया है, जिसमें आपके देखभाल और निगरानी हेतु खुशी नामक ई सगिनी भी उपलब्ध है। जिसमें आप बातचीत कर समस्त समस्याओं को 12 भाषाओं में हल किया जा सकता है।

आर्थिक अभाव में अपना हक न छोड़ने की दी सीख

न्यायाधीश ऋषभ डोनल सिंह ने बताए वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय वारासिवनी में तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड व्यवहार न्यायालय वारासिवनी ऋषभ डोनल सिंह ने की। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार, भरण, पोषण, चिकित्सा सुविधा, शासकीय योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई।



न्यायाधीश ऋषभ डोनल सिंह ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई लोग अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का रुख नहीं कर पाते। विशेषकर जमीन-जायदाद के विवादों में अधिवक्ता की फीस और न्यायालयीन खर्च की चिंता के चलते लोग कई बार अपने अधिकारों के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक संसाधनों के अभाव में किसी व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। पात्र व्यक्ति विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की पुश्तैनी अथवा निजी भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी कारणवश स्वामित्व संबंधी प्रविष्टि में विवाद या त्रुटि सामने आती है अथवा भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न होता हैं, तो आर्थिक परेशानी के कारण व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे मामलों में विधिक सेवा केंद्र से मार्गदर्शन लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। न्यायाधीश ने कहा कि कई परिवारों की जमीन पीढ़ियों से चली आ रही होती है। ऐसी जमीन के राजस्व अभिलेखों में कोई विवाद या त्रुटि सामने आने पर समय रहते कानूनी सलाह लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक अपने अधिकारों की अनदेखी करने से भविष्य में विवाद और जटिल हो सकता है। इसलिए जमीन से संबंधित खसरा, रिकॉर्ड, रजिस्ट्री और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखना चाहिए तथा विवाद की स्थिति में समय पर विधिक सहायता लेनी चाहिए।

तहसीलदार और एसडीएम के बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटा कब्जा

न्याय की चौखट पर दो साल से भटक रहा आदिवासी परिवार

हरिभूमि न्यूज कटंगी।



मध्य प्रदेश में आदिवासियों को जमीन का अधिकार दिलाने के लिए सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। न्याय मिलना कितना कठिन हो गया है, इसकी एक जीती-जागती बानगी कटंगी तहसील के ग्राम उमरी से सामने आई है। यहां एक आदिवासी परिवार दो साल से तहसील, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। तहसीलदार से लेकर एसडीएम न्यायालय ने उनके हक में फैसला दे दिया, बेदखली का आदेश जारी हो गया, लेकिन आज तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ है। कब्जाधारी आज भी उनकी जमीन पर सीना ताने खड़े है और पीड़ति परिवार न्याय की आस में अफसरों की दहलीज नाप रहा है। पूरा मामला ग्राम उमरी के खसरा नंबर 271 और 272/4 का है। पीड़ताि निशा उइके ने बताया कि उनके मामा छयालाल भलावी और उनके भाई विनोद उइके कि यह पैतृक भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में भी जमीन उन्हीं के नाम पर दर्ज है। आरोप है कि गांव के ही दो व्यक्ति दसेलाल आचरे और लालचंद पंचेश्वर ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।

पीडिता के अनुसार, दसेलाल आचरे ने तो कब्जा की हुई जमीन पर पक्का मकान तक बना लिया है, जबकि लालचंद पंचेश्वर ने वहां फाउंडेशन का काम पूरा कर रखा है, जिस पर तहसीलदार द्वारा रोक लगवाई गई। निशा उइके ने बताया कि जब उन्हें कब्जे का पता चला तो वर्ष 2023 में उन्होंने कटंगी तहसीलदार न्यायालय में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रकरण दर्ज कराया। तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के बाद पूरी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया। राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा मौका मुआयना किया गया, जमीन का सीमांकन हुआ और फिर कब्जा चिन्हित किया गया और दोनों पक्षों की पेशी हुई। दोनों पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद तहसीलदार ने पाया कि जमीन पर वास्तव में अवैध कब्जा है। जिसके बाद 03 दिसंबर 2024 को तहसीलदार कटंगी ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत फैसला सुनाते हुए कब्जाधारियों को बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि अनावेदक दसेलाल को उक्त भूमि से बेदखल किया जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच ही एक और चौंकाने वाली बात हुई। जब केस तहसीलदार के यहां चल रहा था, तभी दसेलाल ने तेजी से निर्माण कार्य कर जमीन पर पक्का मकान खड़ा कर लिया, ताकि कब्जा हटाना और मुश्किल हो जाए।

एसडीएम ने भी तहसीलदार के फैसले पर लगाई मुहर: तहसीलदार के बेदखली आदेश के खिलाफ कब्जाधारी दसेलाल आचरे ने एसडीएम न्यायालय में अपील दायर कर दी। इसके बाद यह मामला एसडीएम कोर्ट में चला गया। यहां भी करीब डेढ़ साल तक सुनवाई चली। एसडीएम ने भी सभी दस्तावेजों, सीमांकन रिपोर्ट और तहसीलदार के आदेश का परीक्षण किया। अंततः 09 जून 2026 को एसडीएम ने भी तहसीलदार के फैसले को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी और बेदखली के आदेश को सही ठहराया। यानी दो-दो न्यायालयों ने आदिवासी परिवार के हक में फैसला दे दिया। कानूनी रूप से अब प्रशासन को तुरंत मौके पर जाकर पुलिस बल की मदद से कब्जा हटाकर जमीन पीड़ति परिवार को सौंपनी थी। लेकिन एसडीएम के आदेश को भी तीन महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, फिर भी आज तक जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया है। दबंगों का मकान आज भी वहीं खड़ा है।

दो न्यायालयों के आदेश के बाद भी नहीं हटा कब्जा: सबसे बड़ा सवाल है। जब तहसीलदार और एसडीएम दोनों ने बेदखली का आदेश दे दिया है, तो फिर राजस्व अमला कब्जा क्यों नहीं हटा रहा है? पीड़ति परिवार का आरोप है कि वह लगातार तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन तारीख पर तारीख दी जा रही है। पीड़ति निशा उइके ने रोते हुए बताया, हम आदिवासी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी यही एक जमीन है। हम दो साल से कोर्ट-कचहरी कर रहे हैं। साहब लोगों ने हमारे हक में फैसला भी दे दिया, फिर भी हमें जमीन नहीं मिल रही। हम कहां जाएं? इस पूरे मामले ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। धारा 250 का उद्देश्य ही यह है कि गरीब को त्वरित न्याय मिले। लेकिन जब आदेश के बाद भी सालों तक पालन नहीं होता, तो इस कानून का औचित्य क्या रह जाता है? फिलहाल आदिवासी परिवार ने कलेक्टर बालाघाट से भी गुहार लगाई है कि दो न्यायालयों के आदेश के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम भेजकर उनकी पैतृक जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए और उन्हें कब्जा दिलाया जाए, ताकि उन्हें न्याय का एहसास हो सके।

इनका कहना है-

एसडीएम न्यायालय ने तहसील न्यायालय के फैसला को यथावत रखा है तो पीड़ति बेदखली का आवेदक कार्यालय में लगाएं जिसके बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

पी.एल.सांडिया, तहसीलदार कटंगी

अंतर्राज्यीय 'ऐरागोल्ला गैंग' के तीन शातिर सदस्य गिरफ्तार, 22 लाख के सोने-चांदी के आभूषण बरामद

लांजी के सराफा व्यापारी कपिल आसटकर और राजेगांव गंगालाल करंडे से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा

हरिभूमि न्यूज लांजी।



लांजी थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी कपिल आसटकर से हुई लूट के मामले का बालाघाट पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय 'ऐरागोल्ला गैंग' के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से लांजी और रजेगांव में सराफा व्यापारियों से लूटे गए सोने-चांदी के आभूषणों में से करीब 22 लाख रुपए कीमत का मशरूका बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के नेटवर्क, उनके आने-जाने के रास्तों और वारदात के तरीके का भी पता लगाया।पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने 5 अगस्त 2026 को रजेगांव तथा 28 अगस्त 2026 को लांजी में सराफा व्यापारियों को निशाना बनाया था। दोनों घटनाओं में आरोपियों ने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए व्यापारियों को रास्ते में रोककर लूट की और मौके से फरार हो गए थे। दोनों लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देशन में विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं। पुलिस टीमों ने करीब 65 दिनों तक लगातार जांच और तलाश की। इस दौरान 14 पुलिस टीमों ने लगभग 22,270 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर मध्यप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्रप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आरोपियों की तलाश की।जांच में करीब 21 जिलों में पुलिस टीमों द्वारा खोजबीन, लगभग 190 व्यक्तियों से पूछताछ तथा विभिन्न जेलों में बंद आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की छह जेलों में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की गई, जबकि बालाघाट जेल से दो आरोपियों का पुलिस रिमांड भी प्राप्त किया गया। पुलिस ने वारदात के संभावित मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। रजेगांव से रायपुर तथा आगे ओडिशा की सीमा, संबलपुर और महासमुंद तक करीब 24 स्थानों के कैमरों के फुटेज एकत्र कर आरोपियों के आने-जाने के समय से मिलान किया गया।इसके अलावा लगभग 2,000 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगे 250 से 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का तकनीकी परीक्षण किया गया। पुलिस ने करीब 169 घंटे की सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया।

धान उपार्जन के लिए 94 हजार से अधिक किसानों का हुआ पंजीयन

बालाघाट। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित है। अब तक जिले के 94 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री संत कुमार भलावी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए लालबर्रा तहसील में 14 हजार 427, खैरलांजी में 11 हजार 128, लांजी में 9557, बालाघाट में 9534, कटंगी में 8176, वारासिवनी में 10 हजार 172, बिरसा में 7489, किरनापुर में 9163, परसवाडा में 5653, तिरोडी में 4671 एवं बैहर तहसील में 3902 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है।

खबर संक्षेप

विधायक ने जिला स्तरीय सेवा ज्योति कलश यात्रा एवं सम्मेलन में किया सहभागिता

सिवनी। बुधवार को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी ने जिला स्तरीय सेवा ज्योति कलश यात्रा एवं सम्मेलन मे सहभागिता किया। सिवनी नगर के बींझावाडा रोड स्थित राजतिलक लॉन मे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा और समर्पण भाव को जन-जन तक पहुंचाने हेतु आयोजित जिला स्तरीय सेवा ज्योति कलश यात्रा एवं सम्मेलन में भाजपा विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी ने सहभागिता किया। तथा आयोजित कार्यक्रम मे सांसद श्री फग्गनसिंह कुलस्ते जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन जी, विधायक कमल मर्सकोले जी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डहेरिया जी के साथ द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात भाजपा पदाधिकारियों द्वारा विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान सभी उपस्थितों के साथ श्री राय ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सारगर्भित लाईव उद्बोधन का श्रवण किया।

नव नियुक्त एसडीएम के निर्देशन में गरीबों के अनाज के अवैध भंडारण पर छापामार कार्रवाई

केवलारी। शासकीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गरीब परिवारों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के अवैध भंडारण की सूचना पर नव नियुक्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैघनाथ वासनिक के निर्देशन में 6 अक्टूबर की रात छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान उगली रोड स्थित ड्रीम सिटी कॉलोनी के पास एक मकान से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बरामद कर जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार एसडीएम बैघनाथ वासनिक ने 6 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) कुंवरलाल राऊत को कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलने पर तहसीलदार राऊत ने पटवारी विनोद इनवाती, देवेंद्र मर्सकोले, मायाराम परतेती सहित पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश चौहान के साथ चिन्हित स्थल पर पहुंचकर जांच की।

168 साल पुराना पुल आज भी हजारों लोगों का सहारा, जर्जर सड़क और उगी झाड़ियों ने बढ़ाई परेशानी

ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक पुल प्रशासन की बेरुखी का शिकार

छपारा। आधुनिक दौर में जहां इमारतों की उम्र कुछ दशकों तक सिमटती जा रही है, वहीं छपारा नगर में बैनगंगा नदी पर बना ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक पुल करीब 168 वर्षों से मजबूती के साथ लोगों की आवाजाही का प्रमुख माध्यम बना हुआ है। वर्ष 1858 के आसपास निर्मित इस पुल से आज भी चौबीसों घंटे हजारों लोग आवागमन करते हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।



पुल की करीब आधा किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से सड़क को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पुल के दोनों ओर बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आई हैं। कई स्थानों पर पीपल और बरगद के पेड़ों ने भी जड़ें जमा ली हैं, जिससे पुल का स्वरूप प्रभावित होने के साथ संरचना की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।स्थानीय लोगों के अनुसार पुल की सड़क के सुधार और निर्माण को लेकर स्वीकृति होने के बावजूद अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। नगरवासियों का कहना है कि यह पुल आज भी सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सुरक्षित मार्गों में शामिल है, इसलिए इसकी उपेक्षा उचित नहीं है। लोगों ने प्रशासन से पुल की नियमित देखरेख, झाड़ियों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि यह केवल आवागमन का मार्ग नहीं, बल्कि छपारा की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है।

बंजारी घाट पर कंटेनर ट्रक और कार की भिड़ंत, सात घायल

तीन बच्चे और दो महिलाएं शामिल, प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय सिवनी रेफर

छपारा। सिवनी-लखनादौन के बीच छपारा नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर बंजारी घाट पर बुधवार सुबह कंटेनर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार सात लोग घायल हो गए। घायलों में दो महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय सिवनी रेफर किया गया।



जानकारी के अनुसार हादसा 8 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे हुआ। कार सवार लोग सिवनी से जबलपुर की ओर जा रहे थे और सभी के बिहार निवासी होने की जानकारी सामने आई है। टक्कर की सूचना मिलते ही छपारा की 108 एंबुलेंस और थाना पुलिस की डायल-112 टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा लाया गया।घायलों में सूर्यांश तिवारी, निक्की तिवारी, आर्यन तिवारी, गीत तिवारी, सुनील तिवारी, वर्षा तिवारी, इंद्रजीत तिवारी और सत्यम तिवारी के नाम सामने आए हैं जिनमें बालक सत्यम को सिर पर अधिक चोट आई है । प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला चिकित्सालय भेजा गया। इधर, बंजारी घाट पर अचानक ढलान और पुलिया के पास सड़क की ऊंचाई को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार दुर्घटनाओं के बावजूद इस हिस्से में सड़क सुरक्षा सुधारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सफलता की अनकही कहानी का हुआ नाट्य मंचन

सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते रहे उपस्थित

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत 07 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस सिवनी में 'सफलता की कहानी' का नाट्य मंचन आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन तथा राष्ट्र हित में उनके महान कार्यों से जुड़ी प्रेरक झलकियों ने दर्शक दीर्घा को प्रभावित कर दिया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आमजन को सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना रहा. होप टू पाइंट जीरो एंटरटेनमेंट समूह के करन वासनिक एवं साथियों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सिवनी-मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं हुआ. मोदी सरकार ने देश को 21वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्राचार्य डॉ. रविशंकर नाग ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जीवन और मिशन युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है. कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सेवा संकल्प अभियान के संभागीय संयोजक राजेश त्रिवेदी, गजानन पंचेश्वर, मुकेश बघेल, संतोष नगपुरे डॉ. अभिजीत चौहान, सेवा संकल्प अभियान के जिला संयोजक वीरेंद्र डेहरिया, अल्केश रजक, जिला सेवा संकल्प अभियान के नगर संयोजक संजय सोनी, अनूप मिश्रा और विजय गोलू मिश्रा , पीयूष दुबे, दिनेश कर्वेती, स्वर्णिम साहू, नूर खान और नीलेश जैन उपस्थित रहे. कार्यक्रम का सफल संचालन संयोजक डॉ. सत्येन्द्र कुमार शेन्डे ने किया. कार्यक्रम को सफल बनाने में उप प्राचार्य डॉ. सविता मसीह, डॉ. ज्योति गजभिये, डॉ. मनोज टेंभरे, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. श्याम सिंह राहंगडाले, अमितोष सनोडिया, डॉ. सौरभ सोनी, नरेश डहाके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ सहित यूजी तथा पीजी कक्षाओं के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.



शराब के खिलाफ महिलाओं का हुंकार: रैली निकालकर दी चेतावनी, बोलीं बनाने-बेचने और पीने वालों की खैर नहीं

गोपालगंज। गांव में बढ़ते शराब के चलन के खिलाफ अब महिलाएं खुलकर मैदान में उतर आई हैं। लखनवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालगंज के ग्राम दतनी में करीब आधा सैकड़ा महिलाओं ने एकजुट होकर नशा मुक्ति रैली निकाली और शराब बनाने व बेचने वालों को दो टूक चेतावनी दी। महिलाओं ने साफ कहा कि गांव में शराब का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रैली के दौरान महिलाओं ने पूरे गांव में घूमकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से परिवारों का माहौल बिगड़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर पढ़ने वाले बच्चों तथा बहू-बेटियों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांव को नशामुक्त बनाने के लिए अब महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी और शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा।

महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चली पुलिस

महिलाओं की इस मुहिम को उस समय और मजबूती मिली, जब लखनवाड़ा थाना प्रभारी सीके सिरामे पुलिस स्टाफ के साथ ग्राम दतनी पहुंचे और रैली में शामिल हुए। थाना प्रभारी ने महिलाओं के नशा मुक्ति संकल्प की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

उन्होंने कहा कि शराब बनाने, बेचने और अवैध रूप से पीने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई कि यदि गांव में कहीं शराब बनाई या बेची जा रही है तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें।

सूचना देने वाले को 1100 रुपये का इनाम

थाना प्रभारी सीके सिरामे ने ग्रामीणों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि अवैध शराब बनाने या बेचने वालों की सूचना देकर उन्हें पकड़वाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 1100 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

पुलिस ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वे बेझिझक अवैध शराब से जुड़ी जानकारी पुलिस तक पहुंचाएं। थाना प्रभारी ने कहा कि "लखनवाड़ा पुलिस आपके साथ खड़ी है।"

महिलाओं की एकजुटता बनी चर्चा का विषय

दतनी गांव की महिलाओं की इस पहल की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। महिलाओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने गांव के बच्चों और परिवारों के भविष्य को नशे की गिरफ्त में नहीं जाने देंगी। रैली के दौरान महिलाओं ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर गांव को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।

रैली में लखनवाड़ा थाना प्रभारी सीके सिरामे, आरक्षक अमित रघुवंशी, महिला आरक्षक अंकिता उइके, महिला आरक्षक प्रिया नागेश, 112 वाहन के गगन डेहरिया, पायलट अभिषेक डोंगरे, ग्राम कोटवार सपना मेश्राम, संदीप उइके सहित बड़ी संख्या में ग्राम दतनी की महिलाएं मौजूद रहीं।

महिलाओं की यह हुंकार अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है—गांव को नशामुक्त बनाने की लड़ाई में मातृशक्ति ने साफ कर दिया है कि शराब के खिलाफ उनका अभियान अब रुकने वाला नहीं है।

संकल्प वृक्ष के लिए सिवनी की पावन माटी भोपाल प्रेषित

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय पी.जी. कॉलेज, सिवनी में संकल्प वृक्ष के लिए सिवनी जिले की पावन माटी एकत्रित कर भोपाल प्रेषित किए जाने के अवसर पर गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पी जी कॉलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट पवन कुमार वासनिक ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन डॉ. मोहन यादव जी के निर्देशानुसार आगामी 15 जनवरी, सेना दिवस के अवसर पर संकल्प वृक्ष का रोपण प्रस्तावित है। इस संकल्प वृक्ष के रोपण के लिए प्रदेश के सभी जिलों से माटी एकत्रित कर भोपाल भेजी जा रही है। यह माटी एनसीसी कैडेट्स द्वारा जिला प्रशासन से प्राप्त कर, बटालियन के निर्देशानुसार एनसीसी डायरेक्टरेट, भोपाल को प्रेषित की जाएगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय पी.जी. कॉलेज, सिवनी में 24 म.प्र. बटालियन एनसीसी, छिंदवाड़ा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पी.के. वेलु के मुख्य आतिथ्य एवं निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्यप्रदेश गान के साथ हुआ। इसके पश्चात सेना के वीर जवानों की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य से एनसीसी कैडेट्स प्रत्यूँचा एवं पल्लवी ने सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प वृक्ष हमारे वीर जवानों के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान के साथ-साथ पर्यावरण जागरूकता का भी प्रतीक होगा। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रविशंकर नाग ने एनसीसी कैडेट्स अभिजीत एवं सुवानी को सिवनी की पावन माटी का एक पैकेट सौंपा। वहीं दूसरा पैकेट पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी श्री ओमेश्वर ठाकरे ने कैडेट्स सुरेंद्र एवं अनुप्रिया को सौंपा। यह माटी आगे एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर जबलपुर के माध्यम से एनसीसी डायरेक्टरेट, भोपाल प्रेषित की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ओमेश्वर ठाकरे ने कहा कि एनसीसी टीम द्वारा कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ उन्हें विभिन्न सेवाओं में जाने के अवसर प्रदान करती है तथा युवाओं में एकता और अनुशासन की भावना विकसित करती है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पी.के. वेलु ने कहा कि यह अवसर देश के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने का है। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स एवं युवाओं से इस अवसर से प्रेरणा लेकर निरंतर सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने तथा राष्ट्रसेवा की भावना के साथ भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रविशंकर नाग ने अपनी कविता के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता की भावना जागृत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि "हमारे युवा नदी की धार की तरह होते हैं, वे जिस दिशा में भी आगे बढ़ते हैं, अपना रास्ता बनाने में सक्षम होते हैं।" उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पी.के. वेलु, श्री ओमेश्वर ठाकरे, 24 म.प्र. बटालियन के सूबेदार मेजर निसार सहित सभी अतिथियों एवं उपस्थितजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर अनिल राजपूत, लक्ष्मण पटले, मधुर प्यासी, मनोज यादव, सविता मसीह, रचना राय, लिडिया कुमरे, प्रशांत पाण्डेय, डॉ. हर्षा डेहरिया, विशाल सूर्यवंशी सहित महाविद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।



नशा छोड़ने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और सहनशीलता जरूरी



मुनि श्री 108 निर्वेगसागर जी महाराज के मंगल सान्निध्य में चल रहे मूकमाटी — उपाश्रम की छाँव के प्रवचन में नशा मुक्ति, संयम और सहनशीलता को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। महाराज श्री ने कहा कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले उसके प्रति मन में अरुचि उत्पन्न होना आवश्यक है। केवल बोलने से त्याग नहीं होता, बल्कि त्याग का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। महाराज श्री ने नशे की आदत छोड़ने के उदाहरण से समझाते हुए कहा कि तंबाकू, चाय अथवा अन्य नशीली आदतों को छोड़ने पर शुरुआती दो-चार दिनों में शरीर और मन को परेशानी हो सकती है। सिरदर्द, बेचैनी अथवा असहजता जैसी स्थिति भी बन सकती है, लेकिन व्यक्ति यदि उस कठिन समय को धैर्य और दृढ़ता से सहन कर ले तो धीरे-धीरे वह आदत समाप्त होने लगती है। इसके बाद व्यक्ति स्वयं को अधिक स्वतंत्र और सक्षम महसूस करता है।उन्होंने कहा कि साधना का मार्ग भी प्रारंभ में श्रमसाध्य और कष्टदायी लगता है, लेकिन वही आगे चलकर सुख और आत्मबल का कारण बनता है। नशा छोड़ना भी इसी प्रकार का पुरुषार्थ है। शुरुआत में कठिनाई देखकर व्यक्ति यदि फिर उसी आदत की ओर लौट जाता है तो उसका संघर्ष व्यर्थ हो जाता है।

"जब तक मंजिल न मिले, चलते रहो"

मूकमाटी के कुम्भ और अग्नि-परीक्षा के प्रसंग को समझाते हुए महाराज श्री ने कहा कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त होने तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि "अगर अटक गए तो भटक गए।" नशा मुक्ति के मार्ग पर भी व्यक्ति को शुरुआती परेशानी से घबराने के बजाय अपने संकल्प पर कायम रहना चाहिए।

त्याग की शुरुआत मन की अरुचि से

प्रवचन में कहा गया कि किसी भी विषय या कषाय का वास्तविक त्याग तभी संभव है, जब उसके प्रति अंतरंग से अरुचि उत्पन्न हो। व्यक्ति यदि नशे को हानिकारक मानता है, लेकिन मन के भीतर उसकी इच्छा बनी रहती है, तो वास्तविक त्याग अभी अधूरा है। महाराज श्री ने कहा कि वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, जो व्यक्ति को त्याग की ओर ले जाए। वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी ओर आकर्षण कम होता है और संयम की भावना मजबूत होती है।

सहनशीलता से मजबूत होता है आत्मविश्वास

महाराज श्री ने कहा कि जीवन में आने वाले कष्टों को धैर्यपूर्वक सहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है। "रोते हुए भी सहना है और मुस्कुराते हुए भी सहना है, तो क्यों न मुस्कुराकर सहें।"उन्होंने कहा कि जितना व्यक्ति उचित कठिनाइयों को सहन करना सीखता है, उतना ही उसका विलपावर, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता मजबूत होती है।प्रवचन में अग्नि-परीक्षा के प्रसंग के माध्यम से यह भी बताया गया कि जैसे कुम्भ अग्नि में तपकर अपनी उपयोगिता की ओर बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम रखकर अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। नशे की आदत से मुक्ति के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, सही ज्ञान, सहनशीलता और निरंतर पुरुषार्थ आवश्यक है। कुछ दिनों की कठिनाई को स्वीकार कर व्यक्ति लंबे समय के लिए नशे की गुलामी से मुक्त होकर बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकता है।

सिवनी नगर में 24 के स्थान पर 32 वार्ड किए जाने एवं सीमा वृद्धि की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन



सिवनी। नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन वर्ष 2027 को दृष्टिगत रखते हुए सिवनी नगर पालिका परिषद में वर्तमान 24 वार्डों के स्थान पर 32 वार्ड किए जाने, आवश्यक सीमावृद्धि एवं पुनर्परिसीमन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नेहा मीना जी (भा.प्र.से.) को ज्ञापन सौंपा गया।ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि विगत वर्षों में सिवनी नगर का तेजी से विस्तार हुआ है। नगर की वर्तमान सीमा के आसपास अनेक नवीन कॉलोनियां एवं आवासीय बस्तियां विकसित हो चुकी हैं। बढ़ती जनसंख्या एवं विस्तारित नगरीय क्षेत्र के कारण वर्तमान 24 वार्डों में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का संतुलन प्रभावित हुआ है, जिससे नागरिक सुविधाओं के प्रभावी संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्रत्येक नागरिक तक बेहतर ढंग से पहुंचाने तथा संतुलित नगरीय विकास के लिए वार्डों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है। इसी दृष्टि से 24 वार्डों के स्थान पर 32 वार्डों का गठन, आवश्यक सीमावृद्धि एवं पुनर्परिसीमन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ किए जाने की मांग की गई।ज्ञापन में मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दिनांक 28 सितंबर 2026 के निर्देश तथा जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), सिवनी के दिनांक 29 सितंबर 2026 के पत्र का भी उल्लेख करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजे जाने का अनुरोध किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने कलेक्टर महोदया से मांग की कि सिवनी नगर के वर्तमान विस्तार, बढ़ती जनसंख्या एवं नागरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर सीमावृद्धि, 32 वार्डों के गठन तथा पुनर्परिसीमन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराई जाए, ताकि शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

शुक्रवार को ग्राम टुरिया में आयोजित होगा शहीद मेला

जंगल सत्याग्रह के शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कुरई विकासखंड के ग्राम टुरिया में 09 अक्टूबर 2026 को शहीद मेले का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीद स्मारक में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। जंगल सत्याग्रह में अपने प्राणों को न्योंछावर करने वाले शहीद श्रीमती रेनों बाई, श्रीमती मुड्डे बाई, श्रीमती देभो बाई तथा बिरजू भोई के परिजनों का सम्मान किया जायेगा। शहीद मेले में शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आमजन को प्रदान की जाएगी। मेले के माध्यम से ग्रामीणों एवं उपस्थित नागरिकों को विभिन्न विभागों की योजनाओं, पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने आयोजन के गरिमामय आयोजन को लेकर संबंधित विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी विभागों के जिला अधिकारियों को उनके विभाग में संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी के साथ आयोजन स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

हरिभूमि

सतपुड़ा भूमि

[तिरोड़ी | बोनकटा | कंटगी | बैहर | वारासिवनी | हटा]

जबलपुर, शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026

login : www.haribhoomi.com

लामता में 1186 में सिर्फ 415 किसानों का पंजीयन, अंतिम तारीख पर संकट

सर्वर धीमा, धान खरीदी पंजीयन में अड़ंगा, दो दिन में कैसे होगा हजारों किसानों का पंजीयन?

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

बालाघाट में धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर है। सर्वर धीमा होने से पंजीयन में दिक्कत आ रही है। कलेक्टर कुमार सत्यम के निर्देश के बावजूद समस्या बनी हुई है।



जिले के लामता क्षेत्र में 3000 किसानों में से अब तक केवल 500 किसानों का ही पंजीयन हो पाया है। अंतिम तारीख में सिर्फ दो दिन बचे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।लामता सहकारी साख समिति में पिछले साल 1186 किसानों का पंजीयन हुआ था, इस साल दो और गांव जुड़ने से संख्या बढ़ी है। समिति लिपिक शैलेष कुमार के मुताबिक, सर्वर धीमा होने से एक पंजीयन में करीब आधा घंटा लग रहा है।किसानों ने तकनीकी समस्या के जल्द समाधान और सभी किसानों के पंजीयन की मांग की है। उन्हें आशंका है कि सर्वर की समस्या बनी रही तो कई किसान पंजीयन से वंचित रह सकते हैं।आज तक 1186 किसानों में 415 किसानों का पंजीयन हो पाया है। वह बताते है कि तारीख बढ़ेगी, जब ही किसानों का पंजीयन पूरा हो पाएगा।

ज्ञानेश कुमार कहां मिलेंगे—मोदी की गोद में! नारों से गूंजा बालाघाट, निकाला विशाल मार्च

मतदाता सूची में नाम काटने और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने दिया धरना

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में गुरुवार को बालाघाट में विशाल मार्च एवं धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ मार्च गांधी प्रतिमा तक पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर धरना दिया।इस दौरान कार्यकर्ताओं ने "ज्ञानेश कुमार कहां मिलेंगे—मोदी की गोद में", "वोट चोर—गद्दी छोड़" सहित विभिन्न नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अनुभा मुंजारे ने कहा—लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनआंदोलनः विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कहा कि कांग्रेस द्वारा पूरे देश में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर जनआंदोलन चलाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। यदि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होंगे तो निष्पक्ष चुनाव को लेकर भी चिंता स्वाभाविक है।मुंजारे ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को निर्वाचन आयोग से मिलने की अनुमति नहीं दिए जाने और पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से इन मुद्दों को जनता के बीच उठाती रहेगी।



श्याम पंजवानी बोले—यह लड़ाई लोकतंत्र बचाने की हैः शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर निर्वाचन आयोग से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की।पंजवानी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि जिन मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें नियमानुसार पुनः जोड़ा जाए। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।उन्होंने फॉर्म-6 में कथित बदलावों को लेकर भी सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना था कि यदि किसी स्तर पर कानून का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक विशाल मार्च निकाला गया। गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने धरना देकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शन में श्रीमती अनुभा मुंजारे, श्याम पंजवानी, कैलाश साहू, अंजू जायसवाल, शानू राय, जीतू बर्वे, कुंवर सिंह लाख, नरेंद्र मेश्राम, कारो, बाबूलाल राणा, लिल्हारे, श्रीकृष्ण डीगरू, अफरोज कुरैशी, डॉ. मुकेश वरकड़े, डॉ. दुर्गा वरकड़े, मधु चौकसे, निखिल गौतम, मुकेश माहुल, गुलाब नगपुरे, प्रकाश मदनकर, साबिर मंसूरी, नीटू कौशल, सीमा सिंह, जावेद अली, डॉ. अमर बिसेन, राहुल बेस, जीतू राजपूत, धर्मेंद्र बोपचे, अनिल सोनी, पुष्पलता कुड़वार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कटंगी विधानसभा में पहुंची सेवा ज्योति यात्रा, जगह-जगह हुआ आत्मीय स्वागत

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की सेवा यात्रा के अवसर पर आयोजित सेवा ज्योति यात्रा आज बालाघाट से आगे बढ़ते हुए कटंगी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात यात्रा ने कटंगी विधानसभा के विभिन्न ग्रामों का रुख किया, जहां स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जगह-जगह उत्साहपूर्वक यात्रा का स्वागत किया गया।यात्रा के ग्राम आगरी, लखनवाड़ा, अगासी, उमरी एवं कटंगी नगर के बस स्टैंड पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ आत्मीय स्वागत किया। विभिन्न स्थानों पर नागरिकों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही।

सेवा ज्योति यात्रा के माध्यम से सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है। यात्रा के कटंगी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के दौरान ग्रामों और नगर में स्थानीय नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

विधायक गौरव पारधी ने विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान, सफल आयोजन के लिए व्यक्त किया आभारः कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों एवं कटंगी नगर में सेवा ज्योति यात्रा के आत्मीय स्वागत के लिए विधायक श्री गौरव सिंह पारधी ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के स्वागत के लिए क्षेत्रवासियों द्वारा दिखाई गई सहभागिता उत्साह बढ़ाने वाला है। सेवा और राष्ट्र निर्माण के इस संदेश को आगे बढ़ाने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।विधायक श्री पारधी ने कहा कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाना है। समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से ही इस संकल्प को मजबूत आधार मिलेगा।

परसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 16 लाख पांच हजार रुपए का मशरूका जब्त

कार में 22 किलो गांजा बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज परसवाड़ा।



परसवाड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 22 किलो गांजा, एक कार, दो मोबाइल फोन और 5 हजार रुपए नकद, कुल करीब 16 लाख 5 हजार रुपए का मशरूका जब्त किया है।पुलिस के अनुसार 7 अक्टूबर 2026 को ग्राम भीड़ी से डोरा मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध सफेद रंग की बलेनो कार क्रमांक MP 51 ZE 2932 को रोककर तलाशी ली गई। कार की डिक्की से दो बैग एवं एक प्लास्टिक थैली में करीब 22 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए बताई गई है।मामले में अतुल बिसेन (25), निवासी परसवाड़ा नवेगांव तथा सालिकराम मोमने (60), निवासी बालाघाट कोसमी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 173/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।कार्यवाही में एसडीओपी अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी अनुप कुमार नामदेव के नेतृत्व में उनि घुड़नलाल अहिरवार, सउनि है राजीव जावक सहित पुलिस की समस्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विधायक गौरव पारधी ने उपयोगित जल प्रबंधन परियोजना के कार्य की प्रगति का लिया जायजा



हरिभूमि न्यूज बालाघाट। नगर कटंगी में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत उपयोगित जल प्रबंधन परियोजना (LWM) के कार्य की प्रगति का विधायक गौरव सिंह पारधी ने नगर परिषद के अधिकारियों एवं इंजीनियर के साथ निरीक्षण किया। लगभग 4.26 करोड़ रुपए की लागत एवं 1.50 एमएलडी क्षमता वाली यह परियोजना कटंगी नगर में उपयोगित जल के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।निरीक्षण के दौरान विधायक ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी लेते हुए कार्य की प्रगति एवं निर्धारित समयसीमा के संबंध में अधिकारियों और इंजीनियर से चर्चा की। उन्होंने परियोजना को नगर की स्वच्छता व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कार्य को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर जोर दिया।

विधायक गौरव पारधी ने स्थानीय दुकानदारों एवं रहवासियों से किया संवादः इस दौरान विधायक ने परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय दुकानदारों एवं रहवासियों से संवाद कर कार्य से जुड़ी उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने परियोजना के कार्य से संबंधित विभिन्न समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं। विधायक ने इन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही तथा नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया।

वैज्ञानिक जल प्रबंधन से बेहतर होंगी नागरिक सुविधाएं : उल्लेखनीय है कि 1.50 एमएलडी क्षमता वाली यह परियोजना कटंगी में उपयोगित जल के बेहतर प्रबंधन के साथ नगर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना के पूर्ण होने से जल प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप मिलने के साथ ही नगर में स्वच्छ एवं बेहतर नागरिक सुविधाओं के विकास को भी गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास सर्वे में हुई धांधली, सरपंच रोजगार सहायक के रिश्तेदारों के नाम उजागर

अभी तक नहीं हुई जनसुनवाई में प्रस्तुत शिकायत की जांच, लालबर्रा जनपद के जिम्मेदार अधिकारी शिकायतकर्ता पर शिकायत बंद करने बना रहे दबाव

हरिभूमि न्यूज लालबर्रा।

प्रधानमंत्री आवास के सर्वे और सत्यापन में हुई धांधली पर बांदरी निवासी भारत साहू के द्वारा एक सप्ताह पूर्व सीएम हेल्पलाइन में वह जनसुनवाई में शिकायत की गई थी लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है शिकायतकर्ता ने बताया कि मुझे शिकायत वापस लेने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और जनपद के जिम्मेदार अधिकारी भी शिकायत वापस लेने की बात कर रहे हैं अब सवाल यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच नहीं की जा रही है उल्टे मुझे ही धमकी दी जा रही है की शिकायत वापस ले लो लेकिन मैं जब तक जांच नहीं होती तब तक मैं शिकायत वापस नहीं लूंगा। मैं शिकायत इसलिए की है किबांदरी सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा जरूरतमंद और कच्चे मकान में निवासरत व्यक्तियों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में सरपंच का नाम पात्र हितग्राहियों की सूची में अंकित है वही रोजगार सहायक देवराज बिसेन की पत्नी मीना बिसेन का नाम भी पात्र हितग्राहियों की सूची में सम्मिलित होना जनकल्याणकारी और गरीब हितेषी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार को दर्शाता है।

सर्वे और सत्यापन करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय होः प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों के कल्याण और निम्न तबके के व्यक्ति को पक्की छत का लाभ दिलाना है लेकिन जनपद पंचायत लालबर्रा की ग्राम पंचायत बांदरी में यह योजना अमीरों के लिए चलाई जा रही है.? जिसका ताजा उदाहरण ग्राम पंचायत बांदरी में देखने को मिला जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच का नाम भी पात्र हितग्राहियों की सूची में दर्ज किया जाना सर्वे अधिकारी व सूची का सत्यापन करने वाले अधिकारी की घोर लापरवाही उजागर हुई है जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसे हितग्राहियों का चयन किया जो योजना में अपात्र है जिसमें सरपंच सहित सगे संबंधी और रोजगार सहायक की पत्नी है जो अपात्र है और लालबर्रा में पक्के मकान में अपने पति के साथ निवासरत है फिर भी ऐसे हितग्राहियों का चयन योजना में भारी भ्रष्टाचार है शिकायतकर्ता भारत साहू ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर निष्पक्ष जांच की जाए और प्रधानमंत्री आवास सर्वे में अपने पद का दुरुपयोग करने वाले रोजगार सहायक व सत्यापन अधिकारी पर कठोर कार्रवाई करें जिससे महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कच्चे मकान में रहने वाले गरीब व्यक्तियों को मिले।



वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व का दिया संदेश, 121 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।



वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह 2026 के अंतर्गत वन विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को लेकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 7 अक्टूबर 2026 को वन परिक्षेत्र खैरलांजी (सामान्य) के तत्वावधान में सांदीपनि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खैरलांजी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम मुख्य वन संरक्षक बालाघाट तथा वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बालाघाट के निर्देशन में आयोजित हुआ। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विद्यालय के विद्यार्थियों को वन एवं वन्यप्राणियों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके संरक्षण के बिना पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना कठिन है।

इस दौरान विद्यार्थियों को मानव-वन्यजीव संघर्ष से बचाव एवं सुरक्षा के उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। वन्यप्राणियों के दिखाई देने पर किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए, उनके प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप से बचने तथा वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में रुचि एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में विद्यालय के कुल 121 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यार्थियों ने चित्रों एवं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी समझ और जागरूकता का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के अंत में वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने वन्यप्राणी संरक्षण की शपथ ली। सभी ने वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण तथा मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में वन परिक्षेत्र अधिकारी महर्षि कुमार (आईएफएस प्रशिक्षु), एसडीओ यशपाल मेहरा तथा प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी डी.सी. वासनिक के निर्देशन में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में संजय विश्वकर्मा (डिप्टी), अजय अरजे, दीप्ति, विवेक बंसोड़ (वनरक्षक), सुनील गौतम (वनरक्षक) एवं सौरभ शर्मा (वनरक्षक) सहित विद्यालय के प्राचार्य एस.के. सहारे, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

वन विभाग ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक बनें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करें।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वोकल फार लोकल सहयोग हेतु कार्यक्रम का हुआ आयोजन

हरिभूमि न्यूज किरनापुर।



जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आजीविका मिशन ने किरनापुर में एनआरएलएम की योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रमःमे राधा रानी स्व.सहायतासमूह बम्हनी की महिलाओं ने लगाए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया । सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में गुरुवार को स्थानीय विकासखंड किरनापुर के सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राधा रानी स्व सहायता समूह बम्हनी की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई।की की स्ट्राल में मशरुम उत्पादन पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया। समूह बम्हनी की अध्यक्ष श्रीमती सकिना नंदागौली ने मशरुम के बारे में बताया मशरुम दो प्रकार के होते हैं।बटर मशरुम,अयोस्टर मशरुम। वही अगरबत्ती, मिर्च-मसाला, हल्दी पाउडर, साबुदाना पापड़,सेवई और भी अन्य सामग्री के स्ट्राल लगाए गए जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष ने विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदारी कर राशि दी। सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं को समूह के माध्यम से संचालित गतिविधियों और उपलब्ध अवसरों से परिचित कराया गया। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह ने योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राधा रानी स्व. सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने बनाए स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। अलग-अलग समूहों की महिलाओं ने मेहनत से तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में स्थानीय स्तर पर तैयार वस्तुओं को देखकर मौजूद लोगों ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना की।

26 टीबी मुक्त पंचायतों का जिला स्तरीय समारोह में सम्मान

बालाघाट। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले की विभिन्न विकासखंडों की 26 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत के रूप में गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया।

